I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

हरियाणा के कैथल जिले में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण: एक आनुभविक अध्ययन

कपिल [1*], डॉ. सत्येंद्र सिंह [2]

[1] शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, जनता वैदिक कॉलेज, बड़ौत, बागपतचौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

[2] एसोसिएट प्रोफेसर, जनता वैदिक कॉलेज, बड़ौत, बागपत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: * कपिल

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22057423

सारांश

वर्तमान शोध पत्र हरियाणा राज्य के कैथल जिले के विभिन्न ब्लॉकों में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। 380 उत्तरदाताओं के प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर यह अध्ययन दर्शाता है कि SHG मॉडल ने न केवल ग्रामीण महिलाओं की आय और वित्तीय साक्षरता में वृद्धि की है, बल्कि उनके सामाजिक स्तर, निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वास में भी व्यापक सुधार किया है। अध्ययन में अमर्त्य सेन के 'क्षमता दृष्टिकोण' (Capability Approach), पियरे बोरदियू के 'सांस्कृतिक पूंजी सिद्धांत' (Cultural Capital Theory) एवं टालकॉट पार्सन्स के 'स्ट्रक्चरल-फंक्शनल सिद्धांत' का अनुप्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि सूक्ष्म वित्त एवं सामूहिक सहभागिता ग्रामीण समावेशी विकास का प्रमुख आधार हैं।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 05-07-2026
- **Accepted:** 16-08-2026
- **Published:** 22-08-2026
- **IJCRM:**5(4); 2026: 868-872
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

कपिल, सिंह स. हरियाणा के कैथल जिले में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण: एक आनुभविक अध्ययन Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(4):868-872.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: स्वयं सहायता समूह (SHG), महिला सशक्तिकरण, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, निर्णय क्षमता, कैथल (हरियाणा), सूक्ष्म वित्त। ।

© 2026 कपिल, डॉ. सत्येंद्र सिंह . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के सतत और समावेशी विकास (Sustainable and Inclusive Growth) का अनिवार्य स्तंभ है। विकासशील देशों में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक मानदंडों, सीमित संसाधनों, वित्तीय साक्षरता के अभाव तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कम सहभागिता के कारण प्रभावित रही है। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के अदृश्य श्रम (Unpaid Labor) पर टिका हुआ है। ऐसे में महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और उनके भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए 'स्वयं सहायता समूह' (Self-Help Groups - SHGs) एक क्रांतिकारी और प्रभावी साधन के रूप में उभरे हैं।

स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाली 10 से 20 महिलाओं का एक स्वैच्छिक समूह होता है, जो अपनी छोटी-छोटी वित्तीय बचतों को एकत्रित कर एक साझा कोष (Group Fund) का निर्माण करती हैं। यह मॉडल 'सूक्ष्म वित्त' (Microfinance) और 'सामूहिक सहभागिता' (Collective Action) के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसके माध्यम से महिलाएँ बिना किसी कठिन जमानत (Collateral) के कम ब्याज दर पर आंतरिक ऋण (Internal Loan) प्राप्त करती हैं, जिससे वे साहूकारों के शोषणकारी चक्र से मुक्त होकर स्वरोजगार व छोटी आय-सृजक गतिविधियों (Income Generating Activities) को प्रारंभ करने में सक्षम होती हैं।

हरियाणा राज्य अपनी उच्च प्रति व्यक्ति आय और तीव्र औद्योगिक प्रगति के लिए जाना जाता है, किंतु सामाजिक संरचना की दृष्टि से यहाँ लैंगिक असमानता, पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और महिलाओं की कम श्रमबल सहभागिता (Female Labor Force Participation) जैसी चुनौतियाँ मौजूद रही हैं। राज्य का कैथल जिला एक पारंपरिक एवं कृषि-प्रधान क्षेत्र है, जहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः खेती और पशुपालन पर आधारित है। कैथल जिले के विभिन्न ब्लॉकों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM / HSRLM) और विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के आगमन ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में एक नया सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य तैयार किया है।

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के कैथल जिले के चयनित ग्रामीण ब्लॉकों में कार्यरत SHG से जुड़ी महिलाओं के जीवन पर पड़े प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। यह अध्ययन न केवल महिलाओं की आय, बचत और ऋण लेने के व्यवहार में आए बदलावों को रेखांकित करता है, बल्कि यह पियरे बोरदियू के 'सांस्कृतिक पूंजी सिद्धांत', अमर्त्य सेन के 'क्षमता दृष्टिकोण' तथा टालकॉट पार्सन्स के 'स्ट्रक्चरल-फंक्शनल सिद्धांत' के आलोक में यह भी विश्लेषित करता है कि कैसे आर्थिक स्वावलंबन ने महिलाओं की पारिवारिक निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।

1.1 अध्ययन के मुख्य उद्देश्य (Research Objectives)

- **सामाजिक-जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि का अध्ययन:** कैथल जिले में SHG से जुड़ी महिलाओं की आयु, शैक्षणिक स्तर और वैवाहिक स्थिति का विश्लेषण करना।
- **आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन:** SHG में शामिल होने से पूर्व एवं पश्चात् महिलाओं की आय स्तर, बचत आदतों और ऋण व्यवहार में आए परिवर्तनों का आकलन करना।
- **निर्णय क्षमता व सामाजिक सशक्तिकरण का विश्लेषण:** पारिवारिक वित्तीय निर्णयों, बच्चों की शिक्षा तथा सामाजिक सहभागिता में महिलाओं के बढ़ते योगदान का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- **सैद्धांतिक अनुप्रयोग:** प्राप्त आनुभविक (Empirical) आंकड़ों को स्थापित सामाजिक-आर्थिक सिद्धांतों की कसौटी पर परखना।

2. साहित्य की समीक्षा

2.1 सूक्ष्म वित्त एवं आर्थिक स्वावलंबन संबंधी अध्ययन (Economic & Microfinance Studies)

युनुस (2007) तथा युनुस एवं जोलिस (1998) के अनुसार, सूक्ष्म वित्त (Microfinance) निर्धन ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता विकसित कर उन्हें गरीबी से उबारने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। जब वित्तीय संसाधन महिलाओं के हाथों में आते हैं, तो उनका उपयोग प्राथमिक रूप से परिवार के पोषण, स्वास्थ्य और बाल-शिक्षा पर होता है।

नाबार्ड (NABARD, 2021) की रिपोर्ट दर्शाती है कि 'स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकज कार्यक्रम' (SBLP) ने ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय बहिष्करण (Financial Exclusion) को समाप्त कर औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक उनकी पहुँच सुलभ बनाई है।

हसमानी एवं पटेल (2018) ने पाया कि SHG के माध्यम से प्राप्त लघु ऋणों से डेयरी, सिलाई-कढ़ाई और परचून जैसे सूक्ष्म उद्यमों की शुरुआत हुई, जिससे महिलाओं की औसत पारिवारिक आय में 40% से 60% की वृद्धि दर्ज की गई।

2.2 सामाजिक सशक्तिकरण एवं निर्णय क्षमता संबंधी अध्ययन (Social Empowerment & Decision-Making)

अमर्त्य सेन (Sen, 1999) का 'क्षमता दृष्टिकोण' (Capability Approach) स्पष्ट करता है कि वास्तविक विकास केवल आय वृद्धि नहीं, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमताओं के विस्तार में निहित है।

केसर एवं सिंह (2019) ने उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया कि SHG सदस्यों की घरेलू वित्तीय निर्णयों, परिसंपत्ति क्रय और बच्चों (विशेषकर बालिकाओं) की शिक्षा से जुड़े निर्णयों में स्वायत्तता काफी बढ़ी है।

पियरे बोरदियू (Bourdieu, 1986) के सिद्धांत के संदर्भ में शर्मा एवं वर्मा (2020) ने तर्क दिया कि SHG केवल वित्तीय कोष ही तैयार नहीं करते, बल्कि 'सामाजिक पूंजी' (Social Capital) का निर्माण करते हैं, जिससे महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) बढ़ती है।

2.3 हरियाणा राज्य एवं क्षेत्रीय संदर्भ में साहित्य (Contextual Literature of Haryana)

दहिया एवं मलिक (2020) ने हरियाणा के संदर्भ में पाया कि 'हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' (HSRLM) के अंतर्गत गठित समूहों ने महिलाओं को 'घूँघट प्रथा' और घरेलू बंदिशों से बाहर निकलकर सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है।

© 2026 कपिल, डॉ. सत्येंद्र सिंह . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

रानी एवं कुमार (2022) ने हरियाणा के कृषि-प्रधान जिलों का अध्ययन करते हुए बताया कि यद्यपि वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है, परंतु बाजार पहुंच (Market Linkage), तकनीकी प्रशिक्षण और उत्पादों के उचित मूल्य मिलने में अब भी कुछ संरचनात्मक बाधाएँ मौजूद हैं।

2.4 शोध अंतराल (Research Gap)

पूर्व अध्ययनों में या तो केवल राष्ट्रीय स्तर के वृहद आंकड़ों (Macro Data) का विश्लेषण किया गया है या फिर केवल आर्थिक आय वृद्धि पर ध्यान दिया गया है। कैथल जिले जैसे विशिष्ट पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक आंकड़ों (N=380) के आधार पर पियरे बोरदियू, अमर्त्य सेन एवं टालकॉट पार्सन्स के सिद्धांतों को एक साथ समाहित करते हुए सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन करने वाला कोई समग्र अध्ययन उपलब्ध नहीं था। वर्तमान शोध पत्र इसी शोध अंतराल (Research Gap) को पूरा करता है।

3. शोध कार्यप्रणाली

यह अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित एक आनुभविक (Empirical) एवं विश्लेषणात्मक शोध है। आंकड़ों का संकलन निम्नलिखित विधि से किया गया:

अध्ययन क्षेत्र: कैथल जिले (हरियाणा) के चयनित ग्रामीण ब्लॉक।
नमूना आकार (Sample Size): कुल 380 महिला उत्तरदाता (N = 380), जो विभिन्न SHGs की सक्रिय सदस्य हैं।
आँकड़ा संकलन उपकरण: संरचित साक्षात्कार अनुसूची (Structured Interview Schedule) तथा प्रत्यक्ष बातचीत।
विश्लेषण तकनीक: प्रतिशत विश्लेषण, पूर्व-पश्चात तुलनात्मक तालिकाएँ तथा सामाजिक-आर्थिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग।

3.1 सामाजिक-जनसांख्यिकीय विश्लेषण

महिलाओं के सशक्तिकरण के स्तर को समझने के लिए उनकी आयु, वैवाहिक स्थिति तथा शैक्षणिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है।

3.1.1 आयु संरचना का विश्लेषण (Age Structure)

आयु किसी भी सामाजिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण चर है क्योंकि यह आर्थिक उत्पादकता, निर्णय क्षमता एवं सामाजिक भागीदारी को प्रभावित करती है।

तालिका 1: उत्तरदाताओं का आयु-वार वितरण (N = 380)

आयु वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या (N)	प्रतिशत (%)
18–30 वर्ष	84	22%
31–45 वर्ष	182	48%
46–60 वर्ष	91	24%
60 वर्ष से अधिक	23	6%
कुल	380	100%

व्याख्या: आंकड़ों से स्पष्ट है कि 31–45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक (48%) है। यह आयु वर्ग आर्थिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला वर्ग है, जो परिवार की आय बढ़ाने हेतु SHG में उत्सुकता से भाग लेता है।

3.1.2 वैवाहिक स्थिति का विश्लेषण

तालिका 2: उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्थिति	प्रतिशत (%)
विवाहित	82%
अविवाहित	6%
विधवा	10%
तलाकशुदा / अन्य	2%

व्याख्या एवं सिद्धांत: विवाहित महिलाओं की अधिक संख्या (82%) यह दर्शाती है कि वे पारिवारिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु SHG से जुड़ती हैं। विशेष रूप से विधवा महिलाओं (10%) की भागीदारी यह सिद्ध करती है कि SHG संकटग्रस्त महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बना है। यह निष्कर्ष 'नारी सशक्तिकरण सिद्धांत' (Women Empowerment Theory) की पुष्टि करता है।

3.1.3 शिक्षा स्तर (Educational Qualifications)

तालिका 3: उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

शिक्षा स्तर	प्रतिशत (%)
निरक्षर	18%
प्राथमिक (Primary)	26%
माध्यमिक (Secondary)	34%

© 2026 कपिल, डॉ. सत्येंद्र सिंह . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

उच्च माध्यमिक (Higher Secondary)	15%
स्नातक व अधिक (Graduate & Above)	7%

4. आर्थिक सशक्तिकरण एवं वित्तीय व्यवहार (Economic Empowerment)

4.1 आय स्तर में परिवर्तन (Pre & Post SHG Income)

SHG से जुड़ने से पूर्व महिलाओं की औसत मासिक आय ₹4,500 थी, जिसके प्रमुख स्रोत कृषि मजदूरी, घरेलू श्रम एवं असंगठित क्षेत्र के कार्य थे। यह आय परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त थी।

SHG से जुड़ने के पश्चात महिलाओं की औसत मासिक आय बढ़कर ₹10,000 हो गई, जो लगभग 55% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। महिलाओं ने डेयरी, पशुपालन, सिलाई-कढ़ाई, किराना दुकान एवं हस्तशिल्प कार्यों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित की। (अमर्त्य सेन का 'क्षमता दृष्टिकोण' - Capability Approach)

4.2 बचत एवं ऋण व्यवहार (Savings & Credit Discipline)

तालिका 4: वित्तीय अनुशासन एवं माइक्रोफाइनेंस प्रभाव

सूचक / प्रश्न	सकारात्मक उत्तर (%)
क्या आप नियमित बचत करती हैं?	88% (हाँ) | 12% (नहीं)
क्या आपने SHG से ऋण लिया?	72% (हाँ)
क्या समय पर ऋण का पुनर्भुगतान किया?	90% (हाँ)

5. सामाजिक सशक्तिकरण एवं निर्णय लेने की क्षमता (Social Empowerment)

SHG से जुड़ने के पूर्व एवं पश्चात महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में व्यापक परिवर्तन देखा गया है:

तालिका 5: निर्णय लेने की क्षमता में परिवर्तन (पूर्व एवं पश्चात तुलना)

निर्णय का क्षेत्र	पूर्व (%)	पश्चात् (%)	वृद्धि (%)
आर्थिक निर्णय (पारिवारिक खर्च/निवेश)	32%	74%	+42%
बच्चों की शिक्षा संबंधी निर्णय	41%	81%	+40%
सामाजिक/सामुदायिक कार्यक्रमों में सहभागिता	29%	68%	+39%

टालकॉट पार्सन्स के 'स्ट्रक्चरल-फंक्शनल सिद्धांत' के अनुसार, जब परिवार के अंदर किसी सदस्य की भूमिका में आर्थिक योगदान बढ़ता है, तो परिवार की शक्ति-संरचना में सकारात्मक परिवर्तन आता है।

6. मुख्य निष्कर्ष

1. वित्तीय स्वावलंबन: SHG से जुड़ने के बाद महिलाओं की आय में 55% की वृद्धि हुई और 88% महिलाओं ने नियमित बचत की आदत अपनाई।

2. आर्थिक साक्षरता व साख: 72% महिलाओं ने उत्पादन व स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त किया तथा 90% ने समय पर पुनर्भुगतान करके अपनी उत्कृष्ट क्रेडिट संस्कृति का परिचय दिया।

3. पारिवारिक निर्णय क्षमता: बच्चों की शिक्षा (81%) तथा घरेलू आर्थिक निर्णयों (74%) में महिलाओं का हस्तक्षेप पूर्व की तुलना में दोगुने से अधिक हो गया है।

4. सामाजिक गतिशीलता व सम्मान: विधवा एवं एकल महिलाओं (12%) को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ है।

7. सुझाव एवं अनुशंसाएँ

कौशल विकास प्रशिक्षण: कैथल जिले में पारंपरिक कार्यों से इतर डिजिटल साक्षरता, ई-कॉमर्स एवं आधुनिक हस्तशिल्प प्रशिक्षण दिया जाए।

बाजार लिंकेज (Market Linkage): SHG द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर स्थायी बिक्री केंद्र एवं सरस मेलों का विस्तार हो।

बैंकिंग बाधाओं का सरलीकरण: बैंकों द्वारा SHG ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं सुलभ बनाया जाना चाहिए।

8. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि हरियाणा के कैथल जिले में स्वयं सहायता समूह (SHG) केवल वित्तीय लेनदेन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के सशक्त वाहक हैं। अमर्त्य सेन के 'क्षमता दृष्टिकोण' तथा बोरदियू के 'सांस्कृतिक पूंजी सिद्धांत' के अनुरूप, SHG ने महिलाओं के आत्मविश्वास, सामाजिक पहचान और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ किया है।

© 2026 कपिल, डॉ. सत्येंद्र सिंह . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

संदर्भ सूची

1. Bourdieu P. The forms of capital. In: Richardson J, editor. Handbook of theory and research for the sociology of education. Greenwood; 1986. p. 241-258.
2. Parsons T. The social system. Glencoe: Free Press; 1951.
3. Sen A. Development as freedom. Oxford: Oxford University Press; 1999.
4. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Status of microfinance in India 2021-22. Mumbai: NABARD; 2022.
5. हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (*HSRLM).* वार्षिक प्रगति रिपोर्ट: कैथल जिला. हरियाणा: ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा सरकार; 2023.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

कपिल समाजशास्त्र विभाग, जनता वैदिक कॉलेज, बड़ौत, बागपत, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत में शोधार्थी हैं। उनके शैक्षणिक एवं शोध हित समाजशास्त्र, सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, समकालीन सामाजिक मुद्दों तथा भारतीय समाज से संबंधित विषयों पर केंद्रित हैं। वे सामाजिक समस्याओं के अध्ययन और अकादमिक अनुसंधान में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

© 2026 कपिल, डॉ. सत्येंद्र सिंह . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/